पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख–पत्र

वर्ष 17, अंक 4/2016

सांसदों ने की मोटर वाहन विधेयक 2016 को जल्दी पारित करने की मांग

लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने एक स्वर में 'कट्स' द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'पारफोर' मीटिंग में मोटर वाहन अधिनियम, 2016 को तुरंत पास करने की मांग रखी।

उन्होंने 'आर्थिक नीतियों व मुद्दों पर सांसदों का मंच'(पारफोर), जो कि एक गैर राजनीतिक व विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों पर विचार–विमर्श का एक सशक्त मंच है के माध्यम से यह मांग रखी। सांसदों की इस मीटिंग में मोटर वाहन अधिनियम संशोधन व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा ड्राइविंग लाइसेंसिंग सिस्टम, प्रभावी इलेक्ट्रोनिक क्रियान्वयन में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए।

जी.के. पिल्लई, पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार ने बिल की विस्तृत जानकारी देते हुए मिटिंग की शुरूआत की। जोस के. मणि, सांसद (केरल कांग्रेस) ने कहा कि आजकल सामान्यतः सड़कों की स्थिति अच्छी होने तथा उच्च गति क्षमता के दुपहिया व चौपहिया वाहनों के उपलब्ध होने से काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जिसमें हजारों युवाओं की मौत हो रही है। अतः 'स्पीड गवर्नर' की अनिवार्यता सुनिश्चित होनी चाहिए।

दिनेश त्रिवेदी, सांसद (तृणमूल कांग्रेस) व पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय सड़कों पर

ड्राइविंग काफी डरावनी हो गई है। अतः संयमित वाहन चालन हेतु तकनीकी निगरानी का उपयोग व गैर जिम्मेदार वाहन चालकों में भय पैदा करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब तक हवाई यात्राओं के प्रबन्धन में उपयोग लाई जा रही तकनीकी जैसी तकनीक मोटर वाहन हेतु नहीं लाई जाएगी तब तक इस नए बिल का कोई ज्यादा फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा।

हरीश चन्द्र मीणा, सांसद, भाजपा एवं पूर्व पुलिस प्रमुख, राजस्थान जो कि बिल की प्रमुख समिति के सदस्य भी हैं, ने कहा कि हमें सड़क सुरक्षा के बारे में सोचने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि असली 'रोड़ यूजर' कौन है। क्योंकि सड़क ऐसी जगह है जहां बारात, धरने, प्रदर्शन, पैदल चलने वाले, चौपहिया व दुपहिया वाहन इत्यादि होते हैं। इसमें से असली रोड़ यूजर कौन है, उसको परिभाषित कर उसकी संपूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस हाईवे इत्यादि की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो गांवों कस्बों व शहरों को दो हिस्सों में नहीं बांटे। वर्ना ग्रामीणों का आवागमन बाधित होता है और सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है।

मीटिंग में लोकसभा व राज्यसभा के अन्य सांसदों यथा रंगासायी रामकृष्ण (सांसद कर्नाटक), ला–गणेशन (सांसद मध्यप्रदेश) एन.के. प्रेमचन्द्रन (सांसद केरल), पी.भट्टाचार्य (सांसद पश्चिम बंगाल) व तिरूची सिवा (सांसद तमिलनाडू) ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कई मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि नव सिखिए वाहन चालकों में अल्कोहल सीमा में कमी, सड़क दुर्घटना सहायता कोष की स्थापना, स्टेज कैरिज की अनुमति व बच्चों की सुरक्षा के प्रावधानों की मुखर रूप से मांग की।

'कट्स' के निदेशक जार्ज चेरियन ने कहा कि मीटिंग में सांसदों का उत्साह व चिंता वाहन चालन अधिनियम, 2016 की महत्ता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों व सुझावों को संकलन कर यथाशीघ्र भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा जिससे कि सांसदों की स्वाभाविक चिंता व सुझाव आगामी बिल का हिस्सा बन सके।

इस अंक में...

- करोड़ों रुपए वसूलने में नाकाम अफसर 3
- सरकारी खरीद के लिए पोर्टल 5
- 'मनी कमांडो' पकड़ रहे ब्लैकमनी 6
- बिजली हुई महंगी, ज्यादा आएगा बिल 8
- जल के क्षेत्र में बनें आत्मनिर्भर 9

विमुद्रीकरण से डिजिटल इकोनॉमी को लाभ

सरकार के नोटबंदी के फैसले से देश में डिजिकल इकोनॉमी को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे देश में कैशलेस सोसायटी तेजी से पैर पसारेगी। 'कट्स' इंटरनेशनल के महामंत्री प्रदीप एस महता ने यह विचार 'कट्स' और भारतीय उद्योग परिसंघ 'सीआईआई' की ओर से आयोजित 'उत्तरी राज्य कैसे बने प्रतिस्पर्द्धी' विषयक सेमिनार में व्यक्त किए। उन्होंने कहा देश में डबल डिजिट की ग्रोथ के लिए बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना और उनका वास्तविक विकास जरूरी है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश का विकास भी तेजी से बढ़ेगा।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि यहां लेबर रिफार्म, ई-गवर्नेंस और स्किल डवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में तेजी से सुधार किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए उन्होंने प्रतिस्पर्धा के लिए निपुणता और दक्षता को अनिवार्य बताया।

सेमिनार में अमरीकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा ने भारत और अमरीका के बढ़ते सकारात्मक रिश्तों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत को उद्योगों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिससे मध्य वर्ग व पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जा सके। योजना आयोग के पूर्व सदस्य एवं 'कट्स' के अध्यक्ष अरुण मायरा ने कहा कि विश्व के मुकाबले भारत में रोजगार सृजन की रफ्तार धीमी है। मद्देनजर, रोजगार सृजन पर खास बल देने की आवश्यकता है। 'सीआईआई' राजस्थान काउंसिल के चेयरमैन रजत अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

शहरी निकायों के अधिकारियों के लिए क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित

'कट्स' द्वारा 'राजस्थान सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफार्म' परियोजना के तहत भरतपुर संभाग के शहरी निकायों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए क्षमतावर्धन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन भरतपुर नगर निगम के महापौर शिव सिंह भोंट ने किया। उन्होंने कहा कि 'कट्स' द्वारा राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी निकायों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को आपस में समस्याओं के समाधान के लिए मंच उपलब्ध कराया गया है, जो कि अच्छा प्रयास है। इससे आम नागरिकों को भी लाभ मिल रहा है।

कार्यशाला में डी.सुधाकर, रिटायर्ड इंजिनियर, ग्रेटर हेदराबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने प्रतिभागियों को ठोस कचरा प्रबंधन की तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल कचरे का प्रबंधन होगा, बल्कि नागरिकों का जीवन भी खुशहाल और बेहतर हो सकेगा। साथ ही स्थानीय निकाय ठोस कचरा प्रबंधन से अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

कार्यशाला में 'कट्स' के वरिष्ठ परियोजना समन्वयक अमरदीप सिंह ने परियोजना के तहत राजस्थान के विभिन्न शहरों में की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकायों के विकास के लिए स्वायत शासन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शहरी निकायों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए विभिन्न विषयों पर क्षमतावर्धन कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास

स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन, स्वीडन की आर्थिक सहायता से 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा प्रोओर्गेनिक परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं व उत्पादनकर्ताओं को रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

परियोजना के तहत अक्टूबर से दिसम्बर 2016 के मध्य ग्राम स्तर पर-4, ब्लॉक स्तर पर-25 एवं जिला स्तर पर-7 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा किसानों के लिए चार जिलों में प्रशिक्षण एवं भ्रमण का आयोजन भी किया गया। साथ ही चार जिलों (कोटा, दौसा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़) में जैविक मेलों का आयोजन किया गया। जिनमें उत्पादनकर्ताओं और उपभोक्ताओं को एक मंच प्रदान किया गया तथा जैविक उत्पादों का प्रदर्शन व क्रय-विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मेले में अलग-अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा जैविक खेती के फायदों का भी संदेश दिया गया। सभी कार्यक्रमों में संदर्भ व्यक्तियों एवं कृषि विशेषज्ञों द्वारा जैविक खेती के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई।

करोड़ों रुपए वसूलने में नाकाम अफसर

राजस्थान आबकारी विभाग 1975-76 से अब तक 403 बकायादारों से 197 करोड़ रुपए पसूलने में नाकाम रहा है। इनमें से करीब 40 पर वसूली के लिए कोर्ट में केस चल रहे हैं। वसूली के लिए विभाग ने इन तीस सालों में करीब 10 हजार से ज्यादा नोटिस भेजे, लेकिन किसी भी बकायादार ने या उनके वारिसों ने राशि जमा नहीं कराई।

ठेका लेते समय इन बकायादारों ने अपना व अपने जमानतियों के स्वयं या संपतियों के जो पते विभाग को उपलब्ध कराए थे, जांच में उनमें से अधिकतर अधूरे पाए गए। विभाग बकायादारों से अब संबंधित जानकारियां जुटाने के लिए मुखबिरों की मदद लेने की बात कर रहा है। *(दै.भा., 24.12.16)*

नहीं हुआ आवंटित बजट का उपयोग

समग्र सहकारी विकास परियोजनाओं के लिए सरकार की ओर से प्रथम वर्ष के लिए रिलीज की गई राशि का पूरा उपयोग नहीं होने के कारण सरकार ने द्वितीय वर्ष की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

दरअसल, वर्ष 2015-16 के द्वितीय चरण में क्रियान्वित सीकर, जालौर एवं बांसवाड़ा जिलों की परियोजनाओं को राज्य सरकार की ओर से प्रथम वर्ष 2015-16 के लिए 3836.23 लाख रुपए रिलीज किए गए, इनमें से परियोजनाओं के लिए 576.39 लाख रुपए की ही स्वीकृतियां जारी की गई। ऐसे में वर्ष 2015-16 की राशि का अभी तक पूरा उपयोग नहीं हो सका है। इसके चलते राज्य सरकार द्वारा द्वितीय चरण 2016-17 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। *(दै.न., 05.10.16)*

नहीं हुई लोकपाल की नियुक्ति

देश में 2011 में समाजसेवी अन्ना हजारे के आंदोलन से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बना था। इसके चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 बना और एक जनवरी 2014 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई।

इसके बाद 16 जनवरी को यह कानून लागू हो गया। अब तक करीब 19 राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन लगभग तीन साल बीतने के बाद भी केंद्र में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। कहा जा रहा है कि इसमें कई सियासी पेच फंसे हैं।

यदि ऐसा है तो विधेयक में बदलाव कर तकनीकी कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति में हो रही देरी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। *(रा.प., 24.11.16)*

आदर्श गांव की कछुआ चाल

आदर्श ग्राम पंचायत योजना के चयनित गांवों में विकास कार्यों की कछुआ चाल से ग्रामीण विकास विभाग की चिंता बढ़ने लगी है। अब विभाग पिछड़े जिलों की बेबसी जानकर शेष वित्तीय वर्ष में काम पूरा करने का प्लान तैयार करेगा।

जिला परिषदों से स्वीकृत कार्यों का ब्योरा भी मांगा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास कार्य भी अभी तक कई जिलों में अधूरे पड़े हुए हैं। इस प्लान में अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने की कवायद भी करेगा।

(दै.न., 03.11.16)

हड़प कर रहे गरीबों का राशन

उदयपुर के लक्ष्मणपुरा गांव में गरीबों के राशन का गेहूं आटा मिल मालिक हड़प कर रहे हैं। पकड़े गए ट्रक में 302 कट्टे राशन के गेहूं के थे, जो गोगूंदा क्रय विक्रय समिति को भेजे गए थे। यह गेहूं वहां नहीं पहुंचा। अन्य ट्रक में लदान कर डबोक के लक्ष्मणपुरा आटा मिल में पहुंच गए।

पिछले दिनों प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के मादड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया में भी सगड़ा क्रय विक्रय समिति में राशन के सामान में हेराफेरी का भांडा फूटने के बावजूद यह खेल थम नहीं रहा। आपसी मिलीभगत के चलते मुनाफे का यह खेल लम्बे समय से चल रहा है। इसकी जानकारी रसद विभाग को भी है। लेकिन विभाग के जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। *(दै.न., 02.10.16)*

पानी की जांच में लाखों का खेल

जलदाय विभाग में पानी की जांच के नाम पर लाखों का गड़बड़झाला सामने आया है। विभाग की अलवर प्रयोगशाला में अफसरों ने फर्जी रसीदों से न सिर्फ लाखों रुपए इधर-उधर किए, बल्कि बगैर जांच किए पानी को पीने योग्य घोषित कर हजारों लोगों की जान भी जोखिम में झोंकते रहे।

विभाग में करीब 10 साल से ऐसा चलता रहा लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया। मामला राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंध मंडल की विशेष जांच में सामने आया। जांच में लाखों रुपए के गबन की पुष्टि के बावजूद आला अफसर दोषियों को बचाने में लगे हैं। *(रा.प., 23.12.16)*

गॉज बैंडेज की गुणवता पर सवाल

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में घावों और चोट पर मलहम लगाने के काम आने वाली गॉज बैंडेज की गुणवता पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकारी स्तर पर इनकी प्री जांच के बिना ही अस्पतालों में आपूर्ति की जा रही है। पहले कई बार सरकारी प्रयोगशाला में एक साथ कई नमूने फेल भी हो चुके हैं। लेकिन फौरी कार्रवाई कर इतिश्री कर दी गई।

अब फिर से पहली वाली प्रक्रिया के तहत ही करीब तीन करोड़ रुपए की लागत के गॉज बैंडेज आपूर्ति किए जा रहे हैं। मामले की पड़ताल में सामने आया है कि आपूर्तिकर्ता की ओर से गॉज बैंडेज के नमूनों की जांच अपने स्तर पर निजी प्रयोगशाला में करवाई जा रही है। जबकि सरकारी स्तर पर जांच होने पर कई बार नमूने फेल हो चुके हैं। *(रा.प., 19.10.16)*

टिकट बिक्री में 36 करोड़ का घोटाला

ढ़ाई हजार करोड़ रुपए के घाटे से जूझ रहे राजस्थान रोडवेज में टिकटों की बिक्री में 36 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। यह घोटाला एजी (लेखाकार) की ऑडिट में सामने आया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1547.50 करोड़ की बिक्री हुई, लेकिन रोडवेज के ऑडिट अकाउन्ट में 1511.50 करोड़ रुपए की बिक्री होना बताया।

खास बात यह है कि रोडवेज के वित्त विभाग की ओर से टिकटों से होने वाली आय को लेकर इंटरनल ऑडिट भी कराई जाती है। लेकिन इसमें यह पकड़ में नहीं आया। कयास लगाया जा रहा है कि पहले भी ऐसी गड़बड़ियां हो रही होंगी। सालभर में ही इतनी बड़ी रकम का अंतर वित्त विभाग के गले की हड्डी बन गया है। अब अधिकारी इसकी जांच आईटी व साख्यिकी शाखा के माथे मढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। *(रा.प., 05.10.16, 08.10.16)*

करोड़ों रुपए हो सकते हैं लैप्स

अफसरों की लापरवाही से राज्य के गृह विभाग के करीब 122 करोड़ रुपए लैप्स हो सकते हैं। यह गंभीर मामला अपराधियों का डाटा ऑनलाइन करने और थानों को जोड़ने के सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट का है।

केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के तहत देश भर के थानों को आपस में जोड़कर अपराधियों से जुड़ा पूरा ब्यौरा ऑनलाइन करना है। राजस्थान और बिहार को छोड़ कर अन्य सभी प्रदेशों में यह काम हो चुका है। हाल ही समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि लचर गति के चलते प्रदेश में यह काम ठप्प पड़ा है। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया भी विभाग की इस लापरवाही से काफी खफा है।

(दै.न., 08.12.16)

हाउसिंग बोर्ड के 5000 करोड़ अटके

आय बढ़ाने को लेकर सुस्त रवैया, मकानों की दरों में भारी उछाल, गुणवत्ता की कमी और ग्राहकों की असंतुष्टि। हाउसिंग बोर्ड में पिछले पांच-छह साल से यह सब चलता रहा और सरप्लस मकानों की संख्या बढ़कर 17 हजार तक जा पहुंची। पिछले दिनों सरकार ने बोर्ड की प्रगति जानी तो अधिकारियों ने इन सरप्लस आवासों की जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक, इन मकानों में पांच हजार करोड़ रुपए अटके हुए हैं।

इस बारे में पूरे बोर्ड में कोई भी अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। बोर्ड चेयरमैन ए.मुखोपाध्याय ने यह जानना चाहा कि इतने अधिक बैकलॉग से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है, तो उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। *(दै.भा., 23.10.16)*

मजदूरी में देरी अब ब्याज बकाया

राज्य सरकार ने 2013-14 से 2016-17 के बीच नरेगा मजदूरों को 4701 करोड़ रुपए की मजदूरी का बकाया भुगतान तो कर दिया मगर भुगतान में देरी की वजह से मिलने वाला ब्याज उन्हें नहीं मिला। पिछले चार साल में बकाया भुगतान पर यह ब्याज करीब 25 करोड़ रुपए बनता है। इस बकाया ब्याज में से सिर्फ 27 लाख का ही भुगतान किया है।

केंद्र सरकार और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक राज्य सरकार ने इस बकाया ब्याज का भुगतान नहीं किया है। जिला स्तर पर प्रोग्राम अधिकारियों ने बकाया भुगतान और देय ब्याज की जानकारी स्टेट प्रोग्राम अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। सॉफ्टवेयर से ब्याज की गणना पूरी होने के बावजूद अभी तक बकाया ब्याज के भुगतान की मंजूरी नहीं दी गई। *(दै.भा., 23.11.16)*

आंख मूंद कर पैसा देती रही सरकार

प्रदेशभर में छह साल पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति, सफाई कर्मियों और पिछड़ी जाति के गरीब बच्चों के लिए अनुदानित छात्रावास चलाने हेतु 53 संस्थाओं (राजकीय व गैर राजकीय कॉलेज व स्कूल) को 5.20 करोड़ रुपए भवन निर्माण के लिए दिए गए।

इसके अलावा हर साल 400 से 1600 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से दिए जाते रहे। अब विभाग की जानकारी में आया है संस्थाएं सरकार के इस पैसे का दुरुपयोग कर रही है। सरकार ने अब 26 संस्थाओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 14 संस्थाओं ने तो छात्रावास बनाए ही नहीं, जबकि बाकी छात्रावासों में भी केवल 8-10 बच्चे ही रह रहे हैं।

(रा.प., 09.10.16, 10.10.16)

नहीं बन पा रहे मृदा स्वास्थ कार्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना राज्य में दम तोड़ती नजर आ रही है। प्रदेश में 23.08 लाख मिट्टी के नमूने लेकर 70 लाख मृदा स्वास्थ कार्ड बनाकर किसानों को देने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी तक करीब 30 प्रतिशत से भी कम किसानों के ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने हैं।

किसानों के खेत से लिए गए मिट्टी के नमूनों का परीक्षण प्रयोगशाला में होना था, लेकिन बहुत कम प्रयोगशालाएं होने और पीपीपी मोड पर बनने वाली प्रयोगशालाओं में भी देरी होने से किसानों तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं पहुंच पा रहे हैं। *(दै.न., 11.10.16)*

जलदाय विभाग की धांधली

जलदाय विभाग की स्पेशल प्रोजेक्ट विंग की भरतपुर जोन के इंजीनियरों ने कंपनी को फायदा देने के लिए खुद के एस्टीमेट को ही खारिज कर दिया और 70 करोड़ रुपए ज्यादा में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया।

प्रोजेक्ट की ज्यादा रेट को वाजिब साबित करने और ऑर्डर देने में एक्सईएन व एसई के साथ ही तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर अशोक गर्ग व जी.आर. भाकर शामिल हैं। उन्होंने मिलीभगत कर 192 करोड़ का प्रोजेक्ट एसपीएमएल कंपनी को 262 करोड़ रुपए में दिया। लोगों ने इसकी शिकायत जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी से की लेकिन मामला फाइलों में न्यायसंगत साबित कर दिया गया। मामले में मुख्यमंत्री की लताड़ व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मामला दर्ज कराने पर अब एसपीएमएल कंपनी से काम वापस लेने की तैयारी की जा रही है। इससे कई सवाल उठने लगे हैं। *(दै.भा., 19.10.16)*

लोगों ने किया काले धन का खुलासा

कालाधन उजागर करने की इनकम टैक्स डिक्लेयर स्कीम (आईडीएस) की आखिरी तारीख 30 सितम्बर तक देश में 64 हजार 275 लोगों ने 65 हजार 250 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति की घोषणा की है। इससे सरकारी खजाने में 29 हजार 367 करोड़ रुपए आएगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने योजना के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि यह कोई इम्युनिटी स्कीम नहीं था और इसके तहत अघोषित संपत्ति या आय पर जुर्माना सहित 45 फीसदी कर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि अभी जो आंकड़े दिए गए हैं वे प्रारंभिक है और अंतिम आंकड़े केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जारी करेगा तभी पूरी जानकारी मिलेगी।

(दै.न., 02.10.16)

बढ़ रही है घूसखोरों की पेंडेंसी

प्रदेश में घूसखोरों पर लगाम लगाने वाले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में हर माह पेंडेंसी का भार बढ़ता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल परिवाद और प्राथमिकी की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

माना जा रहा है कि यदि इसी तरह पेंडेंसी बढ़ती रही तो अगले साल में यह संख्या 1000 में पहुंच जाएगी। नवंबर 2016 के अंत तक पेंडिंग मामलों की संख्या 678 हो गई, जबकि 365 मामले नए दर्ज हुए हैं। नवंबर के अंत तक की बात करें तो 830 मामले अभी भी शेष बचे है जिन पर अभी जांच का काम जारी है। *(दै.न., 19.12.16)*

भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा

भ्रष्टाचार से लड़ने से लिए आम जनता को जागरूक होना जरूरी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जनता के सेवक होते हैं। उनको इसके लिए पगार दी जाती है। त्वरित व संवेदनशील प्रशासन सबसे बड़ी जरूरत है।

लोकायुक्त एस.एस. कोठारी ने यह संदेश फागी में आयोजित उपखण्ड स्तरीय आमजन की शिकायतों का निस्तारण करने के मकसद से आयोजित शिविर में देते हुए कहा कि भ्रष्ट व रिश्वतखोर अधिकारी व कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने शिविर में सरकारी योजनाओं की प्रगति, त्वरित कार्रवाई, पेंडिंग मामलों व भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपायों की जानकारी ली। *(दै.न., 03.12.16)*

सरकारी खरीद के लिए पोर्टल

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के तहत मोदी सरकार ने अब सरकारी खरीद के लिए अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह ही ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल लाने का फैसला किया है। अब तक केंद्र सरकार व राज्य सरकारें खरीददारी के लिए टेंडर मंगाती रही है। जिसमें उत्पादों के मूल्य में हेरा-फेरी की गुंजाइस रहती है और भ्रष्टाचार को हवा मिलती है।

माना जा रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल से सरकारी खरीद के सिस्टम के जरिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन खरीद का यह पोर्टल, अमेजन, फ्लिपकार्ट या अन्य ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की तरह ही होगा। इस पर विक्रेता अपने उत्पादों की तस्वीर और मूल्य अपलोड करेंगे। पोर्टल पर उनका उचित मूल्य होगा। इससे खरीद में हेरा-फेरी नही हो सकेगी। नोटबंदी के बाद कैशलेस सोसायटी बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। *(रा.प., 02.12.16)*

काली कमाई की मिलेगी सूचना

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया है कि कालेधन को रोकने में केन्द्र सरकार को कामयाबी मिल रही है। भारत को सितंबर 2019 से स्विट्जरलैंड में भारतीय खाता धारकों की वित्तीय सूची की सूचना मिलने लगेगी। इसके लिए भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सूचना के ऑटोमेटिक एक्सचेंज को लागू करने पर सहमति बन गई है।

विदेशों में कालाधन रखने वालों की स्वदेश स्थित संपत्ति जब्त होगी। इसके लिए फेमा में बदलाव कर प्रावधान किया गया है। अमेरिका के साथ फटका करार किया गया है तथा मलेशिया के साथ दोहरे कराधान संधि को संशोधित किया गया है। अन्य देशों के साथ भी इसी तरह की प्रक्रिया जारी है।

(दै.न., 02.10.16 एवं रा.प., 23.11.16)

बेनामी संपत्तियों की जांच शुरू!

नोटबंदी को लागू करने के बाद केंद्र सरकार की नजर अब देशभर में बेनामी संपत्तियों पर है। इसके लिए सरकार ने महंगी संपत्तियों की जांच का काम शुरू भी कर दिया है। काले धन के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के तहत देश के सभी प्रमुख शहरों के हाईवे के पास की जमीनों की जांच की जा रही है।

इसके अलावा वीआईपी इलाकों में मौजूद महंगी संपत्तियों, प्रमुख औद्योगिक प्लांटो व कामर्शियल फ्लैटों व दुकानों की जांच भी की जा रही है। सरकार ने सभी विभागों से सरकारी जमीनों का भी ब्योरा मांगा है।

सरकार एक सूची बना रही है कि कहां कहां संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। आयकर विभाग और अन्य विभागों की मदद से इन सब संपत्तियों का वेरीफिकेशन किया जा रहा है। इस काम में 200 से ज्यादा टीमें लगाई गई है। *(रा.प., 19.11.16)*

कैसे कसे भ्रष्टाचार पर नकेल

सरकार भले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ होने का दावा करे, लेकिन विभिन्न विभागों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लंबित अभियोजन स्वीकृति कुछ और बयां करती है। सबसे ज्यादा मामले स्वायत शासन विभाग व राजस्व विभाग से जुड़े है।

कई अधिकारियों के खिलाफ वर्षों से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिल रही है। इसमें सिरोही के तत्कालीन कलेक्टर गिरिराज सिंह पर 2005 के एक मामले में अभियोजन स्वीकृति वर्ष 2007 से लंबित है। इसी तरह पीएचडी के कई अधिकारियों के साथ नीरज के पवन व अन्य अधिकारियों के मामले कार्मिक विभाग में लंबित हैं।*(रा.प., 11.12.16)*

सरकार के 'मनी कमांडो' पकड़ रहे ब्लैकमनी

नोटबंदी के बाद सरकार के 'मनी कमांडो' (आईटी, ईडी, आईबी, एयर इंटेलीजेंस यूनिट और पुलिस) देश में ब्लैकमनी रखने वालों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं:

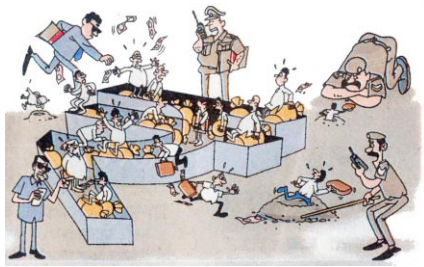

- आईटी डिपार्टमेंट बैंकों से सीधे सूचना ले रही है। बैंक उपभोक्ताओं के खातों में जमा हो रहे पैसों का ब्योरा आईटी को मुहैया कराती है। गड़बड़ी मिलते ही विभाग सक्रिय हो जाता है।
- ईडी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 (फेमा) के तहत अपनी भूमिका निभा रही है। ईडी के काम करने में प्रीवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट 2002 (पीएमएलए) मददगार बन रहा है।
- एआईयू एयरपोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखता है। एआईयू, सीआईएसएफ के साथ काम करता है। इन्हें जैसे ही यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ब्लैकमनी लेकर एयरपोर्ट पर है, तब ये उन्हें धर दबोचते हैं।
- आईबी की खुफिया एजेंसियों की ब्लैकमनी उगाहने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एजेंसी जमीनी स्तर पर सूचना एकत्रित करती है। इस समय बड़ी छापामारियों में आईबी की भूमिका अहम रही।
- धन से जुड़ी हर गतिविधि पर पुलिस नजर रख रही है। किसी को लेकर संदेह पैदा होता है तब पुलिस पूरी तत्परता से छानबीन में लग जाती है। पुलिस अपने मुखबिरों की सूचनाओं पर भी छानबीन कर रही है।
- कुल मिलाकर ये सभी एजेंसियां एक-दूसरे के पूरक के तौर पर काम कर रही है, जिसके नतीजे रोज मिल रहे हैं। *(रा.प., 16.12.16)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
सीकर	बाबूलाल मीणा मोहनलाल परसवाल	एएसआई, दांतारामगढ़ पुलिस थाना, सीकर एडवोकेट, दलाल	50,000	*रा.प. एवं दै.न., 06.10.16*
कोटा	सियाराम माली	कार्यवाहक प्राचार्य, रा. भीमराव अंबेडकर विद्यालय	50,000	*रा.प. एवं दै.भा., 16.10.16*
जयपुर	परमवीर सिंह महीपाल सिंह	उपसभापति,नगर पालिका जोबनेर, जयपुर कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, जोबनेर, जयपुर	60,000	*रा.प. एवं दै.न., 18.10.16*
चूरू	करणाराम बिस्सू विजेन्द्र कुमार	परिवहन उपनिरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय,चूरू दलाल	8,000	*रा.प. एवं दै.न., 18.10.16*
कोटा	रॉबर्ट डिगोलिया प्रवीण कुमार तिवाड़ी	रिटायर्ड वरिष्ठ अनुभाग अभियंता, वेस्टर्न सेंटर रेलवे चीफ वर्क्स मैनेजर, वेस्टर्न सेंटर रेलवे	25,000	*रा.प. एवं दै.भा., 22.10.16*
अलवर	नरेश गजराज सिंह	लिपिक, विद्युत निगम कोटकासिम कार्यालय, अलवर बिजली बिल बांटने वाला ठेकेदार	14,000	*रा.प. एवं दै.न., 26.10.16*
बीकानेर	सुधीर बोर्दिया	प्रवर्तन अधिकारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	50,000	*रा.प., 30.10.16*
नागौर	कैलाशचन्द मीणा	वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (कार्य), रेलवे	20,000	*दै.भा., 05.11.16*
कोटा	अब्दुल हमीद	एएसआई, दुर्घटना थाना, कोटा	15,000	*रा.प. एवं दै.न., 09.11.16*
बारां	पिंकी साहू जितेन्द्र साहू	अध्यक्ष, नगरपालिका, बारां पिंकी साहू के पति एवं सहवरित पार्षद, नगरपालिका	1,00,000	*रा.प.एवं दै.भा., 10.11.16*
भीलवाड़ा	प्रकाश जैन	लिपिक कम कैशियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग	9,000	*रा.प.एवं दै.भा., 22.11.16*
जयपुर	जगदीश प्रसाद	एएसआई, चाकसू थाना, जयपुर	20,000	*रा.प.एवं दै.न., 26.11.16*
दौसा	देशराज मीना	सहायक अभियंता, विद्युत निगम कार्यालय, सिकराय	10,000	*रा.प.एवं दै.भा., 15.12.16*
जयपुर	दिनेश वर्मा	चीफ फॉयर ऑफीसर, मुख्य फॉयर स्टेशन, बनीपार्क	1,50,000	*रा.प.एवं दै.भा., 16.12.16*
प्रतापगढ़	पन्ना लाल	हेड कांस्टेबल, धोलापानी थाना, प्रतापगढ़	10,000	*दै.भा.एवं दै.न., 22.12.16*
झालावाड़	विनय कुमार मंगला	आयकर अधिकारी, आयकर कार्यालय, झालावाड़	1,00,000	*रा.प.एवं दै.भा., 31.12.16*

गरीबी मिटाने की चुनौती स्वीकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश से गरीबी मिटाना एक चुनौती है जिसे उन्होंने स्वीकार किया है और उनकी सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबी मिटाना कठिन काम है। इसे विकास कार्यों के जरिए ही मिटाया जा सकता है।

गरीबी से निजात पाने का एक मात्र उपाय सर्वांगीण विकास है। गरीब को सामर्थ्यवान बनाकर और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी मिटाई जा सकती है। भारत में हुनर की कमी नहीं है। लेकिन इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। *(दै.न., 02.11.16)*

गंदगी के प्रति हो नफरत का माहौल

गंदगी किसी को पसंद नहीं, लेकिन कोई इसे दूर करने की हिम्मत नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के आम लोगों को यह सन्देश देते हुए कहा कि शहर ही नहीं गांवों तक सफाई के प्रति जागरूकता बढ़े, यह जरूरी है।

मोदी ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ प्रधानमंत्री का मिशन नहीं है। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार के साथ-साथ राजनेता, जन-प्रतिनिधियों और आम जन को भी आगे आना होगा। सफाई सिर्फ बजट देने से नहीं आती। उन्होंने कहा जैसे सत्याग्रही देश को गुलामी से आजाद कराता है वैसे स्वच्छाग्रही देश को गदंगी से आजाद कराता है।

(दै.भा., 01.10.16)

फरवरी में पेश होगा आम बजट

इस बार आम बजट एक फरवरी को रखा जाएगा। जिसके मद्देनजर मोदी सरकार ने बजट सत्र जनवरी के अन्तिम सप्ताह में बुलाने का फैसला किया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक व्यक्तव्य में कहा गया है कि आम बजट को एक महीने पहले पेश किया जा रहा है ताकि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को तेजी से अमल में लाया जा सके। इस बार का रेल बजट भी आम बजट के साथ पेश होगा। यानी रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। राज्यों से भी आग्रह किया गया है कि इसका लाभ उठाने के लिए वे अपनी योजनाओं को इसी के अनुरूप आगे बढ़ाएं। *(दै.न., 16.11.16)*

हर संभाग में होगी एग्रीटेक मीट

जयपुर में सम्पन्न हुई ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016 (ग्राम) की तरह अब प्रदेश के सभी संभाग स्तर पर भी एग्रीटेक मीट(ग्राम) होगी। यह घोषणा ग्राम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की।

उन्होंने कहा कि भूमिहीन काश्तकारों को कृषि योग्य भूमि का नियमानुसार आवंटन एवं नियमन किया जाएगा। औषधीय पौधों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, जिन्हें स्किल डवलपमेंट से जोड़ा जाएगा। केन्द्र सरकार के सहयोग से 'स्किल विलें' विकसित किए जाएंगे। कृषि बीमा की रकम 15 दिन में किसान के खाते में पहुंच जाए ऐसी व्यवस्था की गई है।

(रा.प., 12.11.16)

गांवों को बनाया जाए स्मार्ट विलेज

राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि गांवों की उन्नति के लिए शहर के साथ गांव को भी स्मार्ट विलेज बनाया जाए। स्मार्ट विलेज में मूलभूत सुविधाओं के साथ वहां की जरूरत के मुताबिक उद्योग धन्धे हों। इससे स्वरोजगार को बल मिलेगा और वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

उन्होंने स्वच्छता मिशन को सबकी जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि खुले में शौच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। खुले में शौच से बीमारी जंगल से होकर घर तक आती है। सरकार शौचालय बनाने के लिए अनुदान दे रही है, मगर हमें ही बनवाने के बाद उसका सही इस्तेमाल करना होगा।

(दै.न., 05.12.16)

शुरू होगी गरीब कल्याण योजना

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत कोई भी शख्स 50 फीसदी टैक्स और पेनल्टी के साथ अपने अघोषित काले धन का खुलासा कर सकता है। यह स्कीम 17 दिसम्बर से शुरू होकर 31 मार्च, 2017 तक चलेगी।

इसमें उस शख्स की जानकारी को पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। अगर ब्लैक मनी के बारे में खुद ने नहीं बताया और पकड़े गए तो इस पर 75 फीसदी टैक्स और 10 फीसदी पेनल्टी लगाई जाएगी। 25 फीसदी रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जाएगी। गरीब कल्याण योजना में राशि जमा कराने की कोई लिमिट नहीं है। *(रा.प., 17.12.16)*

जन-धन खातों में अब आएगा धन

नोटबंदी के बाद जन-धन खातों में जमा काले धन पर जल्द सरकार कोई फैसला कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बारे में संकेत दिए हैं। उन्होंने एक रैली में कहा कि 'मैं दिमाग खपा रहा हूं कि जन-धन खातों में जमा काला-धन कैसे गरीबों का हो जाए'।

सरकार गरीबों के जीरो बेलेंस खातों में पैसा ट्रांसफर करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। ट्रांसफर होने की रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने रुपए आते हैं। रोजगार योजनाओं पर भी पैसा खर्च होगा जिससे गरीबों को रोजगार मिल सके।

(रा.प., 29.11.16)

तीन साल में बनेंगे एक करोड़ घर

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'हाउसिंग फॉर आल' के तहत अगले तीन साल में एक करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। लोगों के पास अपना खुद का घर हो सके इसके लिए बनाई गई इस योजना में गरीब लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराए जाएंगे।

वर्ष 2022 तक सरकार की 6 करोड़ घर बनाने की योजना है। इसमें दो करोड़ घर शहरों में और चार करोड़ घर गांवों में बनाने की योजना है। सूत्रों के अनुसार कम कीमत में घर खरीदने वालों को सस्ती दर पर होम लोन दिया जाएगा। लोन की दर 7 से 7.5 फीसदी ब्याज के बीच हो सकती है ताकि गरीब आदमी आसानी से घर खरीद सके। इस स्कीम में बनने वाले घरों के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकेंगे। *(रा.प., 18.11.16)*

बिजली हुई महंगी, ज्यादा आएगा बिल

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के फैसले के बाद जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली की नई टैरिफ लागू कर दी है। जिसके कारण हर महीने बिजली उपभोग के आधार पर बिल में 300 से 700 रुपए तक ज्यादा (12 फीसदी तक ज्यादा) चुकाने होंगे। बढ़ी हुई रेट एक सितम्बर से लागू की गई है।

जयपुर,जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम की टैरिफ याचिका पर सुनवाई के बाद विनियामक आयोग ने 22 सितंबर को सभी उपभोक्ता श्रेणियों की बिजली टैरिफ में औसतन 9.6 फीसदी बढ़ोतरी की। इसके बाद जयपुर डिस्कॉम की कॉमर्शियल विंग ने नई टैरिफ से बिल वसूलने के आदेश जारी कर दिए। अब बिलिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट कर बिल जारी किए जाएंगे। *(दै.भा., 03.11.16, 05.11.16)*

'छूट' के डकारे 33.5 करोड़

प्रदेश में खराब मीटर की पीड़ा झेल रहे उपभोक्ताओं की 33.5 करोड़ रुपए की छूट बिजली कंपनियां एक साल में डकार गई। अफसरों ने खानापूर्ति के लिए खराब मीटर नहीं बदले जाने पर पांच फीसदी की छूट देने का फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन बिलिंग साफ्टवेयर में इसको अपडेट ही नहीं किया।

नतीजतन 3.94 लाख उपभोक्ताओं को कई माह तक खराब मीटर की दिक्कतें झेलने के बावजूद बिल में छूट नहीं मिली। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2013-14 की ऑडिट में इस कारस्तानी पर आपत्ति जताई है। मामला विधानसभा में पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बैठक में भी उठ चुका है। लेकिन अफसरों ने यह कह कर पल्ला झाड़ लिया कि अक्टूबर 2015 से साफ्टवेयर में छूट का प्रावधान जोड़ दिया गया है। *(रा.प., 16.10.16)*

भवनों पर लगेंगे सोलर प्रोजेक्ट

केन्द्र सरकार ने राज्य के बड़े क्षेत्रफल वाले सरकारी भवनों की छतों और खाली परिसर में बड़े सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट लगाने में मदद करेगी। राज्य सरकार की सहायता से ऐसे भवनों के प्रस्ताव तैयार होने के बाद प्रोजेक्ट स्थापना में आर्थिक मदद भी मिलेगी।

सरकारी भवनों के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक से 500 किलोवाट क्षमता तक के प्रोजेक्ट लगाने पर विचार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट दायरे में आए भवनों को नेट मीटरिंग से जोड़ने और बिजली उत्पादन की मॉनिटरिंग की व्यवस्था में भी स्टेट नोडल एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से मदद की जाएगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट लगाने के लिए अधिकतम 15 महीने का समय निर्धारित होगा। *(दै.न., 21.12.16)*

बिजली छीजत बढ़ी, हालात अच्छे नहीं

प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां घाटा, छीजत और बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम सुधार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इसके बावजूद जयपुर डिस्कॉम के जयपुर शहर व धौलपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों (सर्किल) में पिछले साल की तुलना में बिजली चोरी बढ़ रही है।

रेवन्यू वसूली में भी कई सर्किल पिछड़ गए हैं। ऐसे में मार्च से अक्टूबर के बीच बिजली छीजत 1.35 फीसदी तक बढ़ गई है। जयपुर सिटी सर्किल में छीजत 1.03 फीसदी और धौलपुर सर्किल में 3.11 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में बिजली की छीजत 28.62 फीसदी है जबकि मार्च के अंत में यह 27.27 फीसदी ही थी। छीजत बढ़ने से प्रबंधन स्तर की मॉनीटरिंग पर सवाल उठने लगे हैं। *(दै.भा., 04.12.16)*

बिजली चोरी पर सच्चाई की मुहर

प्रदेश में बिजली चोरी को लेकर राजस्थान पत्रिका ने जो खुलासा किया था, उस सच्चाई पर आखिरकार मुहर लग गई है। खबर के बाद सर्वे हुआ और रिपोर्ट सामने आई तो बिजली कंपनियों के आला अफसरों की आंखें फटी रह गई। खुद अभियंताओं ने माना है कि अकेले जयपुर डिस्कॉम में 1400 से भी ज्यादा ट्रांसफॉरमर अवैध लगे हुए हैं। जिनके जरिये हर साल करोड़ों की बिजली चुराई जा रही है।

इन अवैध ट्रांसफॉरमर उतारने में अब अभियंताओं के पसीने छूट रहे हैं। एक माह में महज 90 के आसपास अवैध ट्रांसफॉरमर हटाए गए हैं। यह भी सामने आया है कि जितने अवैध ट्रांसफॉर्मर है, उससे ज्यादा तो चोरी हो चुके हैं। दो हजार ट्रांसफॉर्मर तो पिछले छह माह में चोर ले उड़े। इससे करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। *(रा.प., 03.11.16, 06.11.16)*

सौर ऊर्जा का उपयोग अब नहीं महंगा

निजी उपयोग के लिए अब सौर ऊर्जा सस्ती मिलेगी। राज्य सरकार ने तुरंत प्रभाव से विद्युत शुल्क माफ कर दिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्युत शुल्क में छूट 31 मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगी, लेकिन अब तक जमा कराया शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।

सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निजी उपयोग के लिए लगाए जाने वाले और राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के कनेक्टिविटी संबंधी नियमों के तहत जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली लेने पर अब विद्युत शुल्क नहीं लगेगा। इससे नेटवर्किंग का उपयोग कर सौर ऊर्जा से जुड़े परिवारों को बिजली महंगी नहीं पड़ेगी और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। *(रा.प., 17.12.16)*

खराब होने लगी सोलर लाइटें

ग्राम पंचायतों की सोलर लाइटें मरम्मत के अभाव में खटारा होती जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देशों के बावजूद अभी भी मरम्मत का काम फाइलों में ही घूम रहा है। जनप्रतिनिधियों और जिला परिषदों के बीच कई बार लिखित शिकायतों का दौर चलने पर भी कार्रवाई के नाम पर सुस्ती का आलम है।

सोलर लाइटें लगाने में ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार के बाद पंचायतीराज विभाग ने नई सोलर लाइटें लगाने के प्रस्ताव को तो ठंडे बस्ते में ही डाल दिया। अब लाइटें बदहाल होने पर भी नहीं बदली जा रही। समय पर मरम्मत नहीं होने से तकरीबन 25 जिलों के गांवों से रोशनी गायब है। *(दै.न., 19.10.16)*

जापानी तर्ज पर रोकेंगे पानी की छीजत

जयपुर शहर में बढ़ती पेयजल की छीजत को रोकने में जलदाय विभाग अब जापान की मदद लेगा। इसके लिए जापान की तर्ज पर सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही छीजत पर लगाम लगाने के लिए विभाग एक आईटी सेल एवं एनआरडब्लू सेल(नॉन रेवन्यू वाटर) का भी गठन किया जाएगा।

अकेले जयपुर में शहर के कुल पेयजल सप्लाई का लगभग 40 फीसदी पेयजल छीजत में चला जाता है। इससे उपभोक्ता को पूरा पानी नहीं मिल पाता वहीं सरकार को भी राजस्व हानि झेलनी पड़ती है। इसकी रोकथाम के लिए जापान की एजेंसी जाइका से तकनीकी सहयोग लिया है। *(दै.न., 07.10.16)*

पेयजल के लिए केंद्र की मदद जरूरी

प्रदेश में फ्लोराइड की समस्या से निजात दिलाने के लिए निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं पर करीब 14 हजार करोड़ रुपए की देनदारियां सामने आ रही है। मद्देनजर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से शुद्ध पेयजल मुहैया करवाने के लिए 2200 करोड़ रुपए की विशेष सहायता का आग्रह भी किया है। लेकिन प्रस्ताव अभी अधरझूल में है।

जलदाय विभाग की ओर से सतही जल मुहैया करवाने के लिए करीब 15 हजार 490 करोड़ की परियोजनाएं चलाई जा रही है। इन परियोजनाओं से प्रदेश की करीब 15 हजार 180 बस्तियों को शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। *(दै.न., 15.12.16)*

जल संरक्षण पर श्रेणीवार होगा खर्च

राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों को जल संकट से उबारने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के नरेगा प्लान में बदलाव किया जा रहा है। भूजल संरक्षण के कार्यों पर केंद्र मद से उपलब्ध राशि का 65 फीसदी तक खर्च किया जाएगा। डार्क जोन वाले ब्लॉक की राज्य सूची के आधार पर केंद्र ने जल संरक्षण कार्यों की गाइडलाइन भी तैयार कर दी है।

गाइडलाइन में राजस्थान के सामान्य, गंभीर और अति गंभीर श्रेणी के जल संकट वाले इलाकों को चिन्हित किया गया है। इन इलाकों में सभी पंचायत समितियों में भूजल संरक्षण संबंधी कार्य राज्य नरेगा विभाग की मदद से होंगे। जल संरक्षण कार्यों के लिए जमीन चिन्हीकरण, संरचनात्मक ढांचा निर्माण, जल संरक्षण इकाई के प्रकार आदि का निर्धारण राज्य नरेगा विभाग की नोडल एजेंसी के रूप में करेगा। इसके लिए कृषि, सिंचाई, भूजल बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय के अफसरों का सहयोग लिया जाएगा। *(दै.न., 07.11.16)*

समय पर पूरे होंगे प्रोजेक्ट्स–गोयल

जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने विभाग के बड़े प्रोजक्ट्स की समीक्षा के बाद यह स्वीकार किया है कि विभाग के सांचोर व भरतपुर के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करवाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग में 25 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। इनमें से 18 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पिछली सरकार के थे। जबकि महकमे का बजट ही तीन हजार करोड़ था।

बिना बजट के 18 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स डालने से पेंडेंसी बढ़ गई। केंद्र के सहयोग से चलने वाली स्कीम्स का पैसा भी देरी से मिल रहा है। इस कारण से भी कई प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ रही है। अब सभी को फेजवार पूरा किया जाएगा। *(दै.न., 21.12.16)*

जल संरक्षण में जिला परिषदें सुस्त

पंचायतीराज विभाग ने भूजल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 295 पंचायत समितियों में से 204 पंचायत समितियों को डार्कजोन में माना है। जल संरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है, लेकिन ज्यादातर जिला परिषदें इस कवायद को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकीं।

विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि प्रदेश की करीब 70 फीसदी पंचायत समितियों में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सिर्फ फाइलों में दबे पड़े हैं। मानसून गुजर जाने के बाद भी जिला परिषदें जल संरक्षण के सरकारी उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही हैं। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और जिला परिषदों को जिम्मेदारी याद दिलाई है। *(दै.न., 04.11.16)*

प्रदेश में 50 ब्लॉक हुए सेफ

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश के ग्राउण्ड वाटर एसेसमेंट रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2013 में राज्य के मात्र 25 ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में थे। जल स्वावलंबन अभियान की सफलता के बाद यह सेफ ब्लॉक बढ़कर 50 हो गए हैं। इस अभियान ने राजस्थान की तस्वीर बदल दी है।

उन्होंने कहा कि अभियान से चयनित क्षेत्रों के जलाशय आज लबालब हैं, सूखे जोहड़, कुएं और हैंडपंपों में पानी आ गया है। अभियान के पहले चरण की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी को देते हुए कहा कि संग्रहित हुए करीब 11 हजार 170 मिलियन क्यूबिक फीट जल से करीब 41 लाख लोग व 45 लाख पशुधन सीधे लाभान्वित हुआ है। साथ ही अभियान में करीब 26.50 लाख पौधे लगाने का भी ऐतिहासिक काम हुआ है। *(दै.न., 28.11.16)*

जल के क्षेत्र में बनें आत्मनिर्भर

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि जिस ऐतिहासिक सफलता के साथ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का पहला चरण संपन्न हुआ है उससे भी दोगुना जोश और जज्बे के साथ अभियान के दूसरे चरण में सभी को जुटना होगा। तभी हम प्रदेश को जल के क्षेत्र में स्वावलंबी और हरा–भरा बना पाएंगे।

सभी को मिलजुल कर इसे उस चरम तक ले जाना है कि हमें पानी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। अभियान के तहत प्रदेश के 4200 गांवों और 66 नगरीय क्षेत्रों में जल स्वावलंबन के काम होंगे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनी है। इस बार अभियान में शहरों को भी जोड़ा गया है तथा एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। *(दै.न., 28.11.16)*

राज्य में महिलाओं की बढ़ी ताकत

बदलते राजस्थान में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। बीस साल पहले पंचायती राज और निकाय चुनावों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। इससे पहली बार महिलाओं ने घरों की दहलीज लांघ कर नेतृत्व की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। पिछले 20 सालों में महिला साक्षरता में 32.2 फीसदी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

नतीजतन, उनमें सामाजिक व आर्थिक बदलाव भी आया है। अब कामकाजी जगहों पर महिलाएं ज्यादा नजर आने लगी है। महिला प्रोफेशनल्स की संख्या में भी इजाफा हुआ है। स्वरोजगार की दिशा में भी महिलाएं आगे आ रही है।

संसद में महिलाओं का संपत्ति में हिस्सा तय करने के विधेयक को मिली मंजूरी से उनके नाम संपत्ति में 44 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। महिलाओं के नाम से बैंकों में 58 फीसदी खाते खुले हैं। इससे लगने लगा है कि भविष्य की राह और बेहतर होगी।

(दै.भा., 19.12.16)

प्रदेश के मजदूरों को मिलेगी पेंशन

प्रदेश सरकार जल्द ही मजदूरों को पेंशन का बड़ा तोहफा देने जा रही है। इससे साठ की उम्र पार कर चुके मजदूरों को दो जून की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। योजना के तहत रिटायर्ड मजदूरों को प्रति माह एक हजार रुपए पेंशन दी जाएगी।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के माध्यम से यह स्कीम लाई जा रही है। पेंशन योजना श्रम विभाग के अधीन ऐसे रजिस्टर्ड मजदूरों को मिलेगी जो सरकार की तय उम्र, साठ साल को पार कर चुके होंगे। नरेगा में शामिल मजदूरों को भी इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। *(दै.न., 04.11.16)*

चूल्हें के धुएं से मुक्त होगा प्रदेश

राजस्थान अगले 3 सालों में चूल्हे के धुएं से मुक्त हो जाएगा। केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जारी करने की तेज गति से ऐसा लगने लगा है। इस योजना में उतने गैस कनेक्शन तो 6 महीने में ही दे दिए गए जितने अब तक सालभर में दिए जाते रहे हैं।

प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन का आंकड़ा एक करोड़ परिवारों को पार कर गया है। योजना के तहत प्रदेश में एक साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने हैं। अब तक 50 फीसदी से भी अधिक लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। *(रा.प., 22.10.16)*

महिलाओं के लिए अच्छी खबर

गर्भावस्था में इलाज के खर्च से परेशान महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब देशभर में हर गर्भवती महिला के उपचार का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। डॉक्टर इस रिकार्ड को देखकर महीने की नौ तारीख को जांच के लिए खुद घर के नजदीक जाएंगे।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाँच मोबाइल एप व पोर्टल से ऐसा संभव होगा। इससे गंभीर बीमारियों का पता लगा कर कई महिलाओं की जानें बचाई जा सकेगी। योजना की शुरुआत इस साल जून माह में की गई थी, लेकिन अब इसे डिजिटलाइज्ड किया गया है। *(रा.प., 11.11.16)*

महिलाओं को मिलेगी ब्याज में छूट

अल्पसंख्यक महिलाओं को लघु उद्योग व खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज में पूरी तरह छूट मिलेगी। महिला समृद्धि योजना के तहत किसी भी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से वह स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 से 50 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि महिला समय पर ऋण चुकाएगी तभी अंतिम किश्त पर उसे ब्याज की छूट मिलेगी। योजना के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की योजना भी शुरू की गई है। *(दै.भा., 27.10.16)*

पत्नी मां-बाप के प्रति दायित्व नहीं निभाने दे तो हो सकता है तलाक

यह है मामला

मामले के अनुसार कर्नाटक की इस दम्पति की शादी के कुछ दिनों बाद से ही महिला अपने पति पर अकेले रहने का दबाव बना रही थी। उसकी क्रूर हरकतों की वजह से पति ने निचली अदालत में तलाक की अर्जी दी थी। अदालत ने इसे मंजूर कर लिया। बाद में हाईकोर्ट ने महिला का पक्ष लिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला अपने पति को बूढ़े मां-बाप सें अलग रहने को मजबूर करती है तो उसे पति तलाक दे सकता है। कोर्ट ने कहा है कि हिन्दू लॉ के मुताबिक कोई भी महिला किसी भी बेटे को उसके मां-बाप के प्रति दायित्वों के निर्वहन से मना नहीं कर सकती।

जस्टिस ए.आर.दवे और जस्टिस एल.एन राव की बैंच ने कहा कि एक महिला शादी के बाद पति के परिवार की सदस्य बन जाती है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि माता-पिता से अलग रहने की सोच हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है।

कोर्ट ने कर्नाटक के एक दम्पति के तलाक की अर्जी को मंजूरी देते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा बार-बार खुदकुशी की धमकी देना क्रूरता है। यह भी तलाक का आधार हो सकता है। ऐसे में कोई भी पति सकून से नहीं रह सकता न ही पत्नी के इस व्यवहार को सहन कर सकता है। *(रा.प. एवं दै.भा., 08.10.16)*

सड़क सुरक्षा

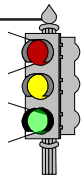

शहर में एक सड़क भी ऐसी नहीं है, जिसे सुरक्षित कहा जा सके

स्मार्ट सिटी बनने जा रहे जयपुर शहर में एक सड़क भी ऐसी नहीं है, जिसे सुरक्षित कहा जा सके। रोड एक्सीडेंट के मामले में जयपुर अन्य शहरों के मुकाबले भी अव्वल है। इस साल के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पिछले 9 माह में 1565 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें से ज्यादातर दुर्घटनाएं रोड कट की गलत डिजाइन की वजह से हुई है। ट्रैफिक पुलिस से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से सितंबर के बीच दुर्घटनाओं में 322 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी वजह लोगों में सिविक सेंस की कमी भी रही है। कुछ दुर्घटनाएं तो तय सीमा से तेज गति से वाहन चलाने के कारण घटी। कई जगहों पर बसों, टैम्पो, टैक्सी में अनियंत्रित सवारियां भरने से दुर्घटना होने से लोग घायल हुए या उनकी मौत हो गई। सड़क हादसों में करीब 70 फीसदी बाइक सवारों की मौत का कारण घटिया हेलमेट है। कई बार एक्सीडेंट तो छोटे होते हैं, लेकिन घटिया हेलमेट के कारण सिर में गंभीर चोट लगने से हादसा बड़ा बन जाता है।

खतरनाक रोड कट की सूची मिलने के बावजूद जेडीए ने लेन सिस्टम सुधारने पर ध्यान नहीं दिया। रोड कट को बन्द भी नहीं किया गया। आखिर ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की गति धीमी करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर में बैरिकेड्स लगा कर लेन सिस्टम बनाया। हालांकि यह जुगाड़ ज्यादा सफल नहीं हो पाया। खास बात यह है कि पुलिस ने इसे गंभीर माना है और जेडीए को सूची देकर कहा है कि वह तकनीकी खामियों को दूर करें। लेकिन अभी भी जेडीए अधिकारी आंखें बन्द किए बैठे हैं।

(दै.भा., 13.10.16, 22.12.16)

वित्तीय सेवाएं

एटीएम का भी होता है बीमा, बैंक बताते नहीं

क्या आपको पता है कि हादसे में किसी की मौत हो जाए और मृतक डेबिट या क्रेडिट कार्ड धारक हो तो उसे 1 से 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा क्लेम मिलना चाहिए। नहीं पता तो आज जान लीजिए क्योंकि सरकारी हो या निजी, बैंक तो कभी बताते ही नहीं कि ऐसा कोई प्रावधान भी है। हादसे के बाद मदद देने-दिलाने वाले पुलिसकर्मियों और जिम्मेदारों को भी इस बारे में प्रायः पता नहीं होता। यही कारण है कि राजधानी जयपुर में ही बीते 8 महीनों में सड़क हादसों में मृत 262 लोगों में से किसी के भी परिवार वालों को ऐसा कोई बीमा क्लेम नहीं मिला। जबकि इनमें से 95 फीसदी लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड धारक थे।

यह है प्रक्रिया...

कार्ड से लेन-देन का बैंक से रिकॉर्ड लेकर बैंक में एक्सीडेंटल क्लेम फॉर्म भरा जाए। हादसे में मौत होने पर एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र व पंचनामा बैंक अधिकारी को दिया जाए। रिजर्व बैंक के अनुसार कार्ड धारक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। हादसे में विकलांगता पर भी क्लेम मिलता है।

बैंक ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ मोबाइल-नेट बैंकिंग सहित अन्य जानकारियां तो देते हैं लेकिन बीमा पॉलिसी के बारे में नहीं बताते। यही कारण है कि हादसे के बाद कई बार हंगामा होने, मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद मिलने के बाद भी कार्ड की बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाली राशि से आश्रित परिवार वंचित रह जाता है।

(रा.प., 01.10.16)

मानक सेवा

लागू होंगे हॉलमार्किंग के नए नियम

नए साल की पहली तारीख से ज्वैलरी हॉलमार्किंग जरूरी हो जाएगा। सरकार ने इसके नए नियम जारी कर दिए हैं। नियमों के मुताबिक एक जनवरी से सिर्फ 22, 18 और 14 कैरेट सोने की ज्वैलरी की हॉलमार्किंग हो सकेगी। गौरतलब है कि अब तक कुल 10 कैटेगरी में हॉलमार्किंग की सुविधा थी, जिसे सरकार ने हटा दिया है।

नए नियम के तहत सोने के सिक्के और बिस्किट का भी स्टैंडर्ड तय होगा। सोने की हॉलमार्किंग उपभोक्ता के हक में है, लेकिन ज्वैलर्स इसका यह कह कर विरोध करते रहे हैं कि देश में हॉलमार्किंग की पर्याप्त सुविधा नहीं है ऐसे में इसे पूरे देश में लागू करना संभव नहीं है। आमतौर पर कीमतों में बेंचमार्किंग न होने की वजह से कम शुद्धता वाले सोने में गोलमाल की आशंका रहती है। कम शुद्धतावाले सोने को खरा सोना बताकर ऊंचे दामों में बेच दिया जाता है। ग्राहक हॉलमार्किंग की मांग करता है तो उन्हें महंगी लागत की वजह भी बताई जाती है। जबकि हॉलमार्किंग की लागत सिर्फ 30 रुपए प्रति नग होती है। सरकार के इस कदम से उपभोक्ता को सोने की शुद्धता की गारंटी मिलेगी और ज्वैलर्स के लिए गोलमाल करने के रास्ते बंद हो जाएंगे।

(दै.भा., 28.12.16)

दूरसंचार सेवाएं

2020 तक होंगे एक अरब मोबाइल ग्राहक

भारत में 2020 तक मोबाइल, ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी के ग्राहकों की कुल संख्या एक अरब हो जाने की उम्मीद है। एक हालिया रिसर्च के मुताबिक, इससे देश की मोबाइल अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास के दौर का पता चलता है। यह अनुमान जीएसएमए इंटेलीजेंस की 'द मोबाइल इकॉनामीः इंडिया 2016' की रिपोर्ट में लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जून 2016 में भारत में 616 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं।

इस हिसाब से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार बन गया है। स्मार्टफोन के मामले में भी 2016 में 27.50 करोड़ स्मार्टफोन उपकरणों के साथ भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोबाइल सुविधाओं और कम होती कीमतों के चलते 2020 तक इसमें 33 करोड़ और उपभोक्ता जुड़ेंगे। इससे देश की 68 फीसदी आबादी के पास मोबाइल सुविधा होगी।

(दै.भा., 30.10.16)

उपभोक्ता फैसले

आवासीय योजना निरस्त की अब देना होगा ब्याज सहित हर्जाना

मानसरोवर निवासी अशोक चौधरी, पत्नी मंजू चौधरी एवं कूकरखेड़ा निवासी सास शारदा देवी ने उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में ओमेक्स लिमिटेड कंपनी (नई दिल्ली) के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने परिवाद में मंच को बताया कि कंपनी के लुभावने विज्ञापन से प्रभावित होकर 2008 में प्लॉट बुक कराए थे। कंपनी ने तीनों को बुकिंग के समय जमा कराई गई अग्रिम राशि की रसीदें भी जारी की थी। लेकिन कंपनी ने 27 सितंबर 2010 को आवासीय योजना निरस्त करते हुए अग्रिम राशि के चैक लौटा दिए। इससे न केवल उनका मकान मिलने का सपना चकनाचूर हो गया बल्कि कंपनी ने उनके पैसे दो साल तक अपने पास जमा रखे और उसका ब्याज भी नहीं दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने मकान का सपना दिखाकर धोखाधड़ी करने, बुकिंग निरस्त करने और जमा राशि पर ब्याज अदा नहीं करने को गंभीर सेवा दोष माना। उपभोक्ता मंच ने ओमेक्स लि. कंपनी (नई दिल्ली) पर एक लाख 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही तीन उपभोक्ताओं के दो साल तक जमा 9 लाख 20 हजार रुपए मय ब्याज के अदा करने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 27.10.16)*

समय पर स्पीड पोस्ट नहीं पहुंची, देना होगा 60 हजार का हर्जाना

जिला उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में भंवर लाल गोरा ने जीपीओ व मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल के खिलाफ अपने वकील के जरिए परिवाद दायर किया। परिवाद में मंच को बताया गया कि परिवादी ने पोस्ट ऑफिस के जरिए स्पीड पोस्ट से 3 अप्रेल 2008 को ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपना आवेदन भिजवाया था। उनका आवेदन 5 अप्रेल को वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन डाक विभाग की लापरवाही से उसका आवेदन समय पर नहीं पहुंचा। उसने डाक विभाग से देरी का कारण पूछा तो सही जवाब नहीं दिया और कहा कि उसे पोस्टल चार्जेज लौटा दिया जाएगा।

उपभोक्ता मंच में मामले की सुनवाई पर विभाग ने दलील दी कि किसी कर्मचारी या अधिकारी ने जान-बूझकर गंतव्य स्थान पर डाक पहुंचाने में देरी नहीं की। वे स्पीड पोस्ट चार्ज 22 रुपए लौटाने के लिए तैयार हैं। मंच ने विभाग की इस दलील को नकारते हुए कहा कि डाक पहुंचने में देरी के कारण परिवादी संभावित नौकरी से वंचित रहा। सिर्फ चार्जेज लौटाने से विभाग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उपभोक्ता मंच ने स्पीड पोस्ट, जीपीओ व मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल को आदेश दिया कि वह भंवर लाल गोरा को 60 हजार रुपए बतौर हर्जाना अदा करें।

(दै.भा., 03.12.16)

स्वच्छ राजस्थान अवार्ड 2016 से मुख्यमंत्री ने किया 'कट्स' को सम्मानित

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 'कट्स' इंटरनेशनल को शहरी सुशासन के तहत नागरिक भागीदारी से शहरी सेवा में सुधार के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए 'स्वच्छ राजस्थान अवार्ड 2016' से सम्मानित किया है। 'कट्स' के जार्ज चेरियन और अमरदीप सिंह ने यह सम्मान स्वायत शासन विभाग द्वारा उदयपुर में भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की सहभागिता से आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्राप्त किया।

'कट्स' ने जयपुर शहर में 'माई सिटी' नाम की परियोजना के तहत सामुदायिक भागीदारी बढ़ाकर शहरी निकायों के माध्यम से की जाने वाली सेवाओं के सुधार हेतु प्रयासरत रहा है, जो नागरिकों की सहभागिता कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। यह कार्यक्रम हितधारकों जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं, नागरिक विकास समितियां, स्थानीय संस्थाएं, स्थानीय निकायों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के कारण संभव हो सका। इससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं के सामाधान के लिए उपलब्ध मंचों द्वारा आम नागरिकों को लाभ मिला व सेवा प्रदाताओं को भी आम जनता से सीधे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

इसके अलावा 'कट्स' द्वारा 'राजस्थान सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफार्म' भी बनाया गया है, जहां राज्य के सभी महापौर, उपमहापौर भाग लेकर आपस में अनुभवों को साझा करते हैं साथ ही नवाचारों पर चर्चा करते हैं। राज्य के शहरी निकायों के अधिकारियों को भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध करावाए जा रहे हैं।

स्त्रोत: रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.513 3259 फैक्स: 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाईट: www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।